Incentives to importers of essential Commodities

122. SHRI T. VENKATRAM REDDY:
SHRI G. PRATHAPA REDDY:

Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether Government have announced special facilities for the import of essential consumer goods in view of the shortage and rising prices of these items; and

(b) whether during the preceding years, wheat, edible oils, pulses, sugar were imported to bring down the rising prices, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) and (b) Under the current Export and Import Policy, as amended, import of wheat is canalised through FCI. Import of white crystal sugar/refined sugar/raw sugar, pulses (except toxic pulses) and all edible oils excluding coco-nut oil, RBD Palm oil, RBD Palm Stearin and palm kernel oil are freely importable.

During 1992-93 a total of 29.90 lakh tonnes (5% more or less at Buyers option) of wheat had been contracted for imports. Against the contracted quantity of 29.90 lakh tonnes, 30.65 lakh tonnes wheat had been received during 1992-93 and 1993-94. Government keeps on reviewing the stock position of foodgrains with it and decision to import foodgrains is resorted to if necessary, to augment availability of foodgrains to meet the requirement of PDS, etc., and to contain open market price. The stock position of foodgrains in the Central Pool continues to be very comfortable. Therefore, there is no need to import foodgrains at present or in immediate future.

During 1994-95 a total quantity of 1.07 lakh MTs of edible oil (Palmolein) was imported by STC for distribution through Public Distribution System. A quantity of about 9.77 lakh tonnes of sugar was also imported by STC & MMTC during 1994-95 for distribution through Public Distribution System. A quantity of 5.5 lakh MTs of pulses was imported into the country under Open General Licence (OGL) in 1994-95.

In order to contain rise in prices of pulses, Government has taken some long-term measures to increase production of pulses and also recently reduced the customs duty on import of pulses from 10% to 5%.

आदिवासी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम

123. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आदिवासी क्षेत्रों के निवासियों के लिए पर्याप्त मात्रा में और समय पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सरकार ने रेगिस्तानी, सूखा प्रवण, आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पहुंच में सुधार करने के लिए वर्ष 1992 में देश में 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की थी। समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं के तहत आने वाले सभी ब्लाक आदिवासी बहुल राज्य तथा असम के उत्तरी कछार और कार्बी एंगलोंग जिले संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आते हैं। केन्द्रीय सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रो के लिए जिन केंद्रीय निर्गम मूल्यों पर खाद्यान्न जारी करती है, वे सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों की तुलना में 50 रु० प्रति क्विंटल कम होते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, उनके द्वारा संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों को किए गए सामान्य आवंटनों के अलावा, इन क्षेत्रों में वितरण के लिए हर